



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2012/अग्रहायण 5, 1934

No. 264]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2012/AGRAHAYANA 5, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

विषय : मलेशिया, चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और अमरीका के मूल के या वहां से निर्यातित सोलर सेल्स, चाहे वे मॉड्यूलों या पैनलों में या कांच या किसी अन्य उप स्तरों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संयोजित या असंयोजित हों, के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/05/2012-डीजीएडी.— यतः सोलर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने मलेशिया, चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सोलर सेल्स, चाहे वे मॉड्यूलों या पैनलों में या कांच या किसी अन्य उप स्तरों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संयोजित या असंयोजित हों, (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए समय-समय यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) ; के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया है, इसलिए प्राधिकारी किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने

और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि वसूल किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार एतद्वारा आरोपित पाटन, घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में जांच शुरू करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोलर सेल्स, चाहे वे मॉड्यूलों या पैनलों में या कांच या किसी अन्य उप स्तरों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संयोजित या असंयोजित हों, हैं। जैसा कि आवेदक ने बताया है, सोलर सैलों का विनिर्माण भारत में दो प्रौद्योगिकियों अर्थात् किस्टेलिन सिलिकॉन प्रौद्योगिकी तथा थिन फिल्म प्रौद्योगिकी के जरिए किया जाता है। दोनों प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादित सोलर सैल विचाराधीन उत्पाद में प्रथम दृष्टया शामिल हैं।

4. सोलर सैल को बाजारी भाषा में फोटोवॉल्टाइक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। फोटो वॉल्टाइक आणविक स्तर पर धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन है। कुछ सामग्रियां फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नाम से ज्ञात एक गुणधर्म का प्रदर्शन करती हैं जिससे प्रकाश के फोटॉन्स का अवशोषण होता है और इलेक्ट्रॉन का निर्गम होता है। जब इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को आवद्ध कर दिया जाता है तो विद्युत धारा निकलती है जिसे विद्युत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रयुक्त सिलिकॉन जैसी अर्धचालक सामग्री में ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है जब हल्की ऊर्जा अर्धचालक सामग्री से टकराती है तो उक्त अर्धचालक सामग्री में अणुओं से इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं। यदि विद्युत चालकों को सकारात्मक या नकारात्मक किनारे से जोड़ दिया जाता है, जो विद्युत सर्किट के रूप में होते हैं, तो किसी विद्युत धारा अर्थात् विद्युत के रूप में इलेक्ट्रॉनों को आवद्ध किया जा सकता है। संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क वर्गीकरण के अध्याय शीर्ष 85414011 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह इस जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग का आधार

5. यह आवेदन मैसर्स इंडोसोलर लि. (100 प्रतिशत ई ओ यू), मै. जूपीटर सोलर पॉवर लि. (डी टी ए यूनिट) और मै. वैबसोल एनर्जी सिस्टम्स लि. (एस ई जैड यूनिट) की ओर से सोलर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं। परंतु आवेदक के दावे के अनुसार संबद्ध देश के अन्य भारतीय उत्पादकों से इस स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया था। प्राप्त उत्तरों से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनमें से अधिकांश ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, किसी प्रतिवादी ने निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है। उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का "एक बड़ा भाग" बनता है। अतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन में उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार संबंधी मानदंड की पूर्ति होती है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाता है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश मलेशिया, चीन जन गण, चीनी ताइपेई और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने सामान्य मूल्य का दावा चीन जन गण हेतु विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान को ध्यान में रखते हुए और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा इसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का आकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार लगाया गया है। जहां तक अमरीका का संबंध है, आवेदक ने एक व्यापार पत्रिका अर्थात् आई एम एस रिसर्च में प्रकाशित कीमत सूचना के आधार पर अमरीका में सामान्य मूल्य का साक्ष्य प्रदान किया है और इस आधार पर अमरीका में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का आकलन किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि इन देशों में घरेलू कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रयास किए गए थे परंतु वह उसे प्राप्त नहीं कर सका। आवेदक ने चीनी ताइपेई और मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य का दावा विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

निर्यात कीमत

9. आवेदक ने ट्रेड इम्पैक्स स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। इसी स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए ध्यान में रखा गया है। निवल कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए प्रथम दृष्टया कीमत समायोजनों की अनुमति दी गई है।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जिससे संबद्ध देशों के बारे में पर्याप्त पाटन मार्जिन का पता चलता है। यह प्रदर्शित करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि

संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन को न्यूनतम सीमा से अधिक आकलित किया गया है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने पाटित आयातों की सर्वाधिक मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास तथा लाभप्रदता में गिरावट एवं वित्तीय घाटे, लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय, घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह आदि के रूप में आरोपित पाटन के कारण हुई "क्षति" के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" का पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य है।

जांच अवधि

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जांच अवधि 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 (12 माह) की है। तथापि, अधिक अद्यतित आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित विश्लेषण किए जाने के लिए प्राधिकारी एतद्वारा जांच अवधि को 1 जनवरी, 2011 से 30 जून, 2012 (18 माह) के रूप में निर्धारित करते हैं। तथापि, क्षति जांच अवधि अप्रैल, 2008-मार्च 2009, अप्रैल, 2009-मार्च 2010, अप्रैल, 2010-मार्च 2011 की अवधि और जांच अवधि शामिल होगी।

शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना

13. आवेदक ने शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है क्योंकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में यह दावा किया गया है कि वह अपेक्षाकृत अल्पावधि में संबद्ध वस्तु के भारी पाटन के कारण हुई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि ऐसे आयातों की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुए जब तक शुल्क की सिफारिश भूतलक्षी प्रभाव से नहीं की जाएगी, तब तक पाटनरोधी शुल्क के अपेक्षित निवारक उपायों को लागू नहीं किया जा सकेगा। हितबद्ध पक्षकार इस बारे में अपने अनुरोध कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से समस्त संगत सूचना दायर करें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस जांच से संगत अनुरोध कर सकता है और निम्नलिखित को लिख सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

समय सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 (चालीस) दिन से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनसे उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से 40 (चालीस) दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा में विस्तार हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे (क) गोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) चिह्नित और (ख) अगोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, प्रश्न संख्या आदि) चिह्नित दूसरे सैट के रूप में दो पृथक सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर "गोपनीय" या "अगोपनीय" उल्लिखित होना चाहिए।

17. किसी चिन्हांकन के बिना प्रस्तुत सूचना अगोपनीय मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय और अगोपनीय रूपांतरण की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता हेतु प्रदत्त सूचना के साथ इस आशय का एक बेहतर कारण संबंधी विवरण प्रदान करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादित परिस्थितियों में

4413 6/12-2

गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत की गई सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है और सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है या वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. किसी सार्थक अगोपनीय सारांश के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में बेहतर कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है। प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत इसका प्रकटन ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार कोयथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2012

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Solar Cells whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates, originating in or exported from Malaysia, China PR, Chinese Taipei and USA.

F. No. 14/5/2012-DGAD.—Whereas Solar Manufacturer's Association (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of Solar Cells whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from Malaysia, China PR, Chinese Taipei and USA (hereinafter referred to as the subject countries), for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from subject countries, and injury to the domestic industry, and causal link between the dumping and injury, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is Solar Cells whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates. As stated by the applicant, Solar Cells are manufactured through two technologies in India i.e. crystalline silicon technology and thin film technology. Solar cells produced through both the technologies are prima facie covered under the product under consideration.

4. Solar cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic is the direct conversion of sun light into electricity at the atomic level. Some materials exhibit a property known as the photoelectric effect that causes them to absorb photons of light and release electrons. When these free electrons are captured electric current results, which can be used as electricity. Semiconductor materials such as silicon used in microelectronics industry possess such photoelectric effect. When light energy strikes the semiconductor material, electrons are knocked loose from the atoms in the semiconductor material. If electrical conductors are attached to the positive and negative sides, forming an electrical circuit, the electrons can be captured in the form of an electric current i.e. electricity. The subject goods are classified under Customs Classification chapter heading 8541 40 11. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

5. The application has been filed by Solar Manufacturer's Association on behalf of M/s Indosolar Ltd (100% EOU), M/s Jupiter Solar Power Limited (DTA unit) and M/s Websol Energy Systems Ltd (SEZ unit). There are a number of other producers of the subject goods in India. But, as claimed by the applicant, the other Indian producers of the subject goods are themselves importers of the subject goods from the subject countries. In this context, the Authority had made efforts to ascertain the position from other known Indian producers. From the responses received, the Authority notes that most of them have acknowledged to have imported the subject goods from the subject countries during the POI. However, none of the respondents provided the required information in the prescribed format. From the available information, the Authority prima facie notes that the production of the applicant accounts for "a major proportion" of total production of the product under consideration in India. The Authority, therefore, prima facie determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

LIKE ARTICLE

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are like articles to the goods produced by the domestic industry. There are no

differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are prima facie treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

COUNTRIES INVOLVED

7. The countries involved in the present investigation are Malaysia, Peoples Republic of China, Chinese Taipei and United States of America.

NORMAL VALUE

8. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted for China PR. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. As regards USA, the applicant has provided evidences of Normal Value in USA based on price information published in a trade magazine namely IMS Research and estimated the Normal Value of the subject goods in USA on this basis. The Applicant has submitted that best possible efforts were made to procure evidences of domestic price in Chinese Taipei and Malaysia and however they could not procure any. Applicant has claimed Normal Value for Chinese Taipei and Malaysia on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

EXPORT PRICE

9. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from Trade Impex Statistics Services. The data from the same source has been taken into consideration for the injury period including the POI. Price adjustments have been prima facie allowed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and bank charges to arrive at the net ex-factory export price.

4413 6/12-3

DUMPING MARGIN

10. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject countries. There is prima facie evidence to show that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

INJURY AND CAUSAL LINK

11. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price depression and decline in profitability and financial losses, negative return on capital employed, cash flow, etc, of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation (POI) proposed by the applicant was 1st January 2011 to 31st December 2011 (12 months). However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as 1st January 2011 to 30th June 2012 (18 months). The injury investigation period will however cover the periods April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 2011 and the POI.

RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES

13. The applicant has requested for retrospective imposition of duty as the injury is claimed to be caused to the domestic industry by massive dumping of subject product in relatively short time. They have further submitted that considering the huge volume of such imports, unless duty is recommended retrospectively, the desired remedial measures of anti-dumping duties may not be accomplished. The interested parties may make their submissions in this regard.

SUBMISSION OF INFORMATION

14. The known exporters in the subject countries and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant

information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi -110011.**

TIME LIMIT

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

22. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

NON-COOPERATION

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority